पर दबाव डालकर आई.डी.पी.एल. की रक्षा करें। यह मैं मांग करता हूं। धन्यवाद।

RE: DECLINING STANDARDS IN ffIN-DI FILMS BROADCAST BY DOOR-DARSHAN

श्री संजय निरुपम (महाराष्ट्र): थैंक्यू मैडम आपने मुझे मौका दिया जीरो आवर में अपना विषय रखने के लिए। मैं आपके माध्यम से दूरदर्शन पर जो हिंदी फिल्में दिखायी जाती हैं उनके गिरते स्तर की ओर पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस विषय पर पहले भी बहुत सदन में बोला गया है और सदन के बाहर भी बोलाय गया है। हर रमय यह विचार निकालकर आता है कि हिंदी फिल्मों मेंम बहुत ज्यादा सेक्स बायोशेंस आ गया है जबकि हिंदी फिल्मों का क्या उद्देश्य है इस पर डिबेट नहीं की जा सकती है बहस नहीं की जा सकती है। कोई विलयर कट गिडलाइंस भी नहीं है हिंदी फिल्म प्रोड्यूसर्स के पास। लेकिन दूरदर्शन के पास एक बिलयर कट गाइडलाइन है कि उनके जो भी प्रोग्राम हैं उन्हें जो भी फिल्में दिखानी है उनका अंतिम उद्देश्य मनोरंजन और शिक्षा होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से दूरदर्शन पर ऐसे फिल्में दिखायी जाती हैं जिनसे न तो मनोरंजन हो रहा है और न ही उनसे दर्शकों का किसी तरह का शिक्षण हो पा रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए सदन की जानकारी के लिए कुछ फिल्मों की सूची लेकर आया हूं। उनमें से एक फिल्म है, मेरा

मुकद्दर जो हाल के वर्ष में दिखायी गयी थी। एक है, गजब तमाशा, बाज। एक फिल्म है, मेरा लहू एक फिल्म है सिरफिरा। उसके अलावा कुछ फिल्में है-सुराग, बात बन जाए, लाट साहब, मंगल पांडे, रानी और लालपरी, डबल क्रास, लव एण्ड गाड, आशा ज्योति, अनोखी रात...

उपसभापति: आप बड़ी पिक्चरें देखते हैं दूरदर्शन पर।

श्री संजय निरुपण: मैं लिस्ट देने के बाद इसकी कुछ वजह बताऊंगा ...(**व्यवधान**)... कि आखिर क्यों यह फिल्म की लिस्ट इस तरह से बनी। मैं इसकी वजह बता रहा हूं। मैडम, मैं जिन फिल्मों की सूची आपके सामने रख रहा हूं, इन फिल्मों को दिखाता कौन है दूरर्दशन पर। मैं यह बताना चाह रहा हूं। इन सारी फिल्मों को प्रदर्शित करने का अधिकार सिर्फ एन.एफ.डी.सी. के पास है, नेशनल फिल्म डिवलपमेंट कार्पोरेशन के पास है। दूरदर्शन हर हफ्ते अपने विभिन्न चैनलों पर तकरीबन 19 फिल्में दिखाता है, तकरीबन या कुल 19 फिल्में दिखाता है। 19 फिल्मों में से 17 फिल्में एन.एफ.डी.सी. दिखाती है, मैडम,। मेरा कहने का मतलब यह है कि सिर्फ दो फिल्मों के लिए प्राइवेट प्रोड्यूसर्ज एप्रोच करते हैं, अपने प्रोपोजल देते हैं और दूरदर्शन उनको क्लीयर करता है। मंत्री महोदय सदन में हमारी बीच में बैठे हुए हैं। ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति: आई एंड बी के ताल्लुक से सवाल है। It is good that he is mentioning it in the House, the films which are shown on Doordarshan are not good films according to him because he has seen all of them. These are not for families. So, pay attention, please.

श्री संजय निरुपम: तो माननीय मंत्री जी महोदय जरा ब्यान दें कि दूरदर्शन पर पिछले कुछ सालों में जो फिल्में दिखाई गई हैं ...(**व्यवधान**)...

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI S. JAIPAL REDDY): I am consulting Ram Jethmalaniji.

श्री संजय निरुपम: मुझे सुनने के बाद उनकी कंसल्ट कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। ...(**व्यवधान**)... तो माननीय मंत्री महोदय मैं कहना यह चाह रहा था कि दूरदर्शन पर हर हफ्ते अपने विभिन्न चैनलों पर कुल 19 हिन्दी फिल्में दिखाता है। उन 19 फिल्मों में से 17 फिल्में एन.एफ.डी.सी. के थ्रू आती है। सिर्फ दो फिल्मों के लिए प्राइवेट प्रोड्यूसर अपने स्तर पर संपर्क कर पाते हैं प्रोपजल रखते हैं, उनको क्लीयर करके दो फिल्में दिकाने का मौका मिलता है। 17 फिल्में एन.एफ.डीसी. को देने के पीछे यानी इस मोनोपली के पीछे क्या औचित्थ है, यह समझ में नहीं आता? एक तरफ इस देश में प्राइवेटाइजेशन की ट्रेड चल रही है, लहर चल रही है। वित्त मंत्री महोदय बोलते हैं हम सारी चीजों को प्राइवेटाइज करेंगे। प्राइवेटाइजेशन के पीछे जो तर्क दिया जाता है वह यह है कि इससे कंपीटीशन बढ़ता है। कंपीटीशन से गुणता सामने आती है। ...(**व्यवधान**)... एक मिनट, गुरुदास दासगुप्ता जी, जरा एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। आप लोग इतने

सीनियर लोग हैं। इतना बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ सुनता रहता हूं तो कभी आप लोग भी सुनिए। तो मंत्री महोदय, मैं आपको यह बताना चाह रहा ता कि एन.एफ.डी.सी. को एक तरह का मोनोपली दे दी गई है। इस एन.एफ.डी.सी. की मोनोपसी से तीन खतरे मुझे दिखते हैं। एक तो यह कि दूरदर्शन पर जो 17 फिल्में आ रही हैं वह सिर्फ एन.एफ.डी.सी. तय करती है। इससे क्वलालिटी गिरती जा रही है क्योंकि एन.एफ.डी.सी. को कौन सी फिल्म दिखानी है यह दूरदर्शन नहीं कहता एन.एफ.डी.सी. को जो फिल्में सही लगती हैं, जो फिल्में मिल जाती है जो प्रोड्यूसर के साथ बातचीत होती है वह लाकर दिखा देते हैं। दूसरी बात यह रही है कि एन.एफ.डी.सी. बीच में एजेंट का रोल प्ले करने लगी है। अगर प्राइवेट प्रोड्यूसर्ज को बोला जाए कि आप अपनी फिल्म लेकर आईये, अपने प्रोपोजल लेकर आइये हम इसको देखेंगे और उनके बाद क्लीयर करेंगे तो यह वय्वस्था नहीं है। एन.एफ.डी.सी. ब्रोकर का3 काम करने लगा है। इस ब्रोकरेज की वजह से करप्शन बढ़ रहा है, इमोरल, एक्टीविटीज डिवैलप होती है। मेरे ख्याल से हर माननीय व्यक्ति सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि अगर दो पार्टी के बीच में एक एजेंट डिवैलप कर दिया जाए तो वहां से किकबैक शुरू होजाता है। वहां पर दलाली खाने की प्रथा शुरू हो जाती है और मुझे बहूत शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि एन.एफ.डी.सी. में इस तरह के कामकाज, इस तरह की एक्टिवलिटीज शूरू हो गई है। एन.एफ.डी.सी. अच्छे प्रोड्यूसर्स को एप्रोच नहीं करती, अच्छी फिल्मों के लिए तलाश नहीं करती, उसके पास जो प्रोड्यूसर्ज जाते हैं कुछ कमीशन देने की बात करते हैं उन फिल्मों को फाइनल कर देती है। वे फिल्में बाद में दूरदर्शन को दे दी जाती है। जो खतरे हैं उनमें सब से बड़ा खतरा है कि दूरदर्शन के सामने आज कोई आप्शन नहीं रह गया है। एन.एफ.डी.सी. जो फिल्में दे देती है उसे दूरदर्शन दिका देता है। मंत्री महोदय, आपसे मेरी मांग यह है कि टी.वी. पर जो हिन्दी फिल्में दिखाई जा रही हैं उसके लिए ओपन बिडिंग हो जाए। सारे प्रोड्यूसर्ज के सामने आप अपील दे दीजिए कि आप अपने अपने प्रोपोजल लेकर आइये। जो फिल्म अच्छी होगी और हमारे गाइडलाइंस पर खरी उतरेंगी वे फिल्में हम दिखायेंगे। दूसरी बात यह होगी कि दूरदर्शन पर हिन्दी फिल्मों पर कंट्रोल रखने के लिए, उसकी गुणवत्ता पर नियंत्रण रखने के लिए किस तरह की कमेटी बनाए, उसमें दूरदर्शन के आफिसर्ज तो हो ही इसके अलावा कुछ अच्छे आर्टिस्ट, इंटैलेक्चुअल, कुछ अच्छे राम जेठमलानी जैसे जो वकील है वे भी उसमें हों ताकि इन फिल्मों की नियमित 4-4,5-5 फिल्मों की एक स्क्रीनिंग हो। वह कमेटी उस फिल्म को देखे, रेव्यू करे, उसके बाद डिसिजन ले कि यह फिल्म दूरदर्शन पर दिखाने लायक है या नहीं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना वह विषय यहां समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री रेणुका चौधरी (आंध्र प्रदेश): फैमिलीज को देखना चाहिए स्कीनिंग कमेटी में, हाउस वाइव्ज को देखना चाहिए क्योंकि उनको पता है कि फैमिली में दिखा सकते हैं या नहीं। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय निरुपमः उसमें लेडीज़ भी होंगी, घबराइये मत। ...(**व्यवधान**)...

उपसभापतिः रेणुका जी, मंत्री जी खड़े हैं।

SHRI S. JAIPAL REDDY: Madam, our hon. Member raised a Starred Question/ yesterday which was not reached. We complement him on being resourceful. He has circumvented that and raised the question.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Chair is also involved in it because it is very concerned with such films being shown on Doordarshan.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Now, let me address myself to his first concern about vulgarity and violence in the films screened on Doordarshan. I share his confern, but I must take him into confidence and, through you, the whole House about the procedure adopted by Doordarshan in the matter. They only select films which receive a certificate called 'U'—universal—how inversal it is, it is a different matter. No film which receives that wonderful certificate 'A'—adults only— is ever allowed to be screened on Doordarshan. Apart from this precuation, Doordarshan also adopts the procedure of getting the U-films filtered further through a preview commitee. In Sipte of that, some of these films survive and appear on the screen. But, that is a larger part of it. If I begin to curb vulgarity, my friend Ram Jethmalani will come down heavily on me

because he will try to draw a distinction j or he will try to tell me that there is not much distinction between liberty and j vulgarity. But, that is a larger question. ...*(Interruptions)...I* am not saying that. He is a champion of liberaty. There are honest people divided on this question. I am not holding any view. I am merely bringing to the attention of the House various views held by intellectuals honestly on this issue.

Then, he referred to the question of fiims being taken from NFDC. This was the figure I gave to the House yesterday. NFDC supplies 19 films per week.

SHRI SANJAY NIRUPAM. Seventeen films.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Yes, seventeen. You are right. But, out of these 17 films, only one films is shown on DD-I. The rest are shown on DD-3—Movie Club and DD-International, and both these channels are commercially unviable channels. NFDC has lost six crores of rupees in 1996-97 for doing this. Therefore, the private parties are not prepared to do service on DD-3 which is a Movie Club and DD-International. The private parties went to MRTPC...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, you are so informative on this question, but I must remind you that this is Zero Hour.

SHRI S. JAIPAL REDDY: I know that.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We have other Memebrs also. ...*(Interruptions)...*

SHRI S. JAIPAL REDDY: Since he has raised the question...

श्री संजय निरुपमः मैं एन.एफ.डी.सी. की मोनोपली के बारे में जानना चाहता हूं। **...(व्यवधान)...**

SHRI M.A. BABY (Kerala): The Minister has been so generous.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Let us have a full discussion on this issue one day.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Madam, I would like to disabuse the hon. Member of the notion that the NFDC has been in any way favoured. The NFDC, has incrurred a loss of rupees six crores in one year. ...*(Interruptions)...*

SHRI SANJAY NIRUPAM: That is about other channels, except Metro Channel. My question related to Metro Channel.

श्री राज बब्बर (उत्तर प्रदेश)**:** मैडम, माननीय सदस्य का कहना है कि एन.एफ.डी.सी. की मोनीपॉली की वजह से यह किकबेक की सिचूएशन पैदा हो गयी है। सवाल यह नहीं है कि कितनी फिल्मों का घाटा उन को उठाना पड़ रहा है, घाटे का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि एक एजेंसी फिल्मों को खरीदती है और दूसरी एजेंसी बेचती है **...(व्यवधान)...**

श्री संजय निरुपमः मैं जानना चाहता हूं कि उस की जरूरत क्या है?

SHRI S. JAIPAL REDDYi I am coming to those questions.

The point is what is in demand. The DD-I channel alone is in demand. So far as the DD-I channel is concerned, the share between NFDC and private parties is almost 50:50. It is almost* 50:50 and the supply from the private parties has not been good. They made a commitment in regard to two films—*sadma* and *Chan-dramukhi* but they did not supply and the NFDC had to rush to rescue Doordar-shan. As far as vulgarity is concerned, it is a larger issue and I have to still look into that. The matter is under consideration of the MRTPC. When the MRTPC gives a final decision, we will review the whole matter.

श्री संजय निरुपमः मैडम, इसमें एक दो बातें छूट गई हैं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Sanjay, please take your seat. The duty

of the chair is while giving protection to one Member for raising an issue, the Chair has to keep in mind that there are other names also. I cannot allow you to monopolise,however important it is. I will not allow even the Minister to monopolise at the expense of other Members. …(Interruptions)… We are again mono-polists.

RE : LEAKAGE OF QUESTION PAPERS FOR I.I.T. ENTRANCE TEST

SHRI BRATIN SENGUPTA (West Bengal): Madam, it has already been discussed in this House that an astronomical amount of national investment is made for the IITs of our country in order to build a modern and ancient advanced India. But this year the academic session of all six IITs has been dislocated and significantly delayed. The reason for this is known to all of us. In Lucknow primarily and then in Patna as well, through the private coaching centres, the. mathematics question, .paper was leaked one day in advance. Physics and chemistry question papers were leaked on the days of the examination. For the first time in the history of IIT under-graduate entrance tests this has taken place. The exams have been postponed and, therefore, the session is going to be disclocatcd. I can't say whether with two sets of question papers the same thing could not have repeated but there has been an unprecedented phenomenon in the history of ITT this time also as far as paper-siettmg is concerned. Only one set of question papers was set this time, if the news reported in the newspapers is correct. In the last three years, since the UPSC civil services question paper leakage to the CBSC question paper leakage this year, this has become almost a national epidemic. I am constrained to say so. I hope, it would be national concern for all guardians, students and anybody who is concerned with the human capital development of our country. My only intention in raising this matter is to try to explore the possibility of the Government's reaction to it. Thank you.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI (Uttar Pradesh): Madam Deputy Chairman, I just want to add something to what has been said by my young colleague and this is about UTs and other institutions. In the recent past the question papers have been leaked out causing havoc to the academic standards and to education in the country. All the newspapers have recently reported about the IIT leakage and joint entrance examination. This morning there was a news item about Roorkee Engineering College, also j recognised as an institution equivalent to IIT. Only some time back there was a discussion in which my friend Shri Sengupta had participated. It was raised by my colleague Satish Agarwal. It was about CBSE examinations. Earlier also UPSC question papers had been leaked out. It is an unfortunate thing. I do not treat them as stray incidents or isolated incidents. This indicates the kind of deterioration that has been creeping in in the academic world and in the monitoring that is so necessary. That is why the matter needs much more serious attention of the Ministry of Human Resource Development. Madam Deputy Chairman, there are long-term implications to what has been happening.

Now it has come out that it is the coaching institutions 'which are spreading a network thoughout the country. I know something about it in the northern India. I was told about all these things by many people in Allahabad, Lucknow, Delhi, etc. But, I did not believe them till I found these reports in the Press and after having verified some of these further facts. There is a mafia growing. In these coaching institutions huge sums, astronomical sums of money are just being extracted. The unfortunate thing is* that many teachers of colleges and universities are taking classes in these coaching institutions. They are not attending their